

अध्याय 06 : संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र

भाग I → 01 से 04

संघ

केंद्रशासित

प्रमुख अनुच्छेद

राज्यों का पुनर्गठन

वर्तमान राज्य

- धर आयोग (जून 1948)
- JVP समिति (दिसंबर 1948)
- फजल अली आयोग (दिसंबर 1953)
- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

अनुच्छेद 1 —
संघ का नाम
और राज्यक्षेत्र

अनुच्छेद 2 — नए
राज्यों का प्रवेश
या स्थापना

अनुच्छेद 3 — राज्यों का निर्माण
तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या
नामों में परिवर्तन

अनुच्छेद 4 — पहली व चौथी
अनुसूची में संशोधन तथा
अनुषंगी मामले

Chapter 06 : The Union and Its Territory

Part 1 → 01 to 04

States

Union Territories

Key Articles

Reorganization

Present

- Dhar Commission (June 1948)
- JVP Committee (December 1948)
- Fazal Ali Commission (December 1953)
- States Reorganisation Act, 1956

Article 1 — Name
and Territory of
the Union

Article 2 — Admission
or Establishment of
New States

Article 3 — Formation of States
and Alteration of Areas, Boundaries
or Names of Existing States

Article 4 — Amendment of the
First and Fourth Schedules and
Supplemental Matters

1) सामान्य परिचय

भाग का नाम	संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory)
सम्मिलित अनुच्छेद	अनुच्छेद 1 से 4 (कुल 4 अनुच्छेद)
संबंधित अनुसूचियाँ	पहली अनुसूची (राज्य व संघ राज्यक्षेत्र की सूची) एवं चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटों का आवंटन)
वर्तमान स्थिति (2026)	28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश



1) General Introduction

Name of the Part	The Union and its Territory
Articles Included	Articles 1 to 4 (Total 4 Articles)
Related Schedules	First Schedule (List of States and Union Territories) and Fourth Schedule (Allocation of seats in Rajya Sabha)
Current Status (2026)	28 States and 8 Union Territories



2) प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र (Name and Territory of the Union)

- 1) देश के औपचारिक नाम
 - भारत
 - इंडिया

1(1): "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा।"
- 2) राज्य व उनके राज्यक्षेत्र
 - प्रथम अनुसूची
 - संघ (Union) ⇒ राज्य मात्र
 - राज्यक्षेत्र (Territory) ⇒ राज्य + केंद्र शासित प्रदेश + अर्जित (acquired)
- 3) राज्यों का संघ
 - राजपद्धति का प्रकार
 - कनाडा से प्रभावित
 - राज्य का संघ ✓
 - "राज्यों का परिसंघ" (Federation of States) ✗

- समझौते का परिणाम नहीं
 - राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं
 - विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

2) Key Articles

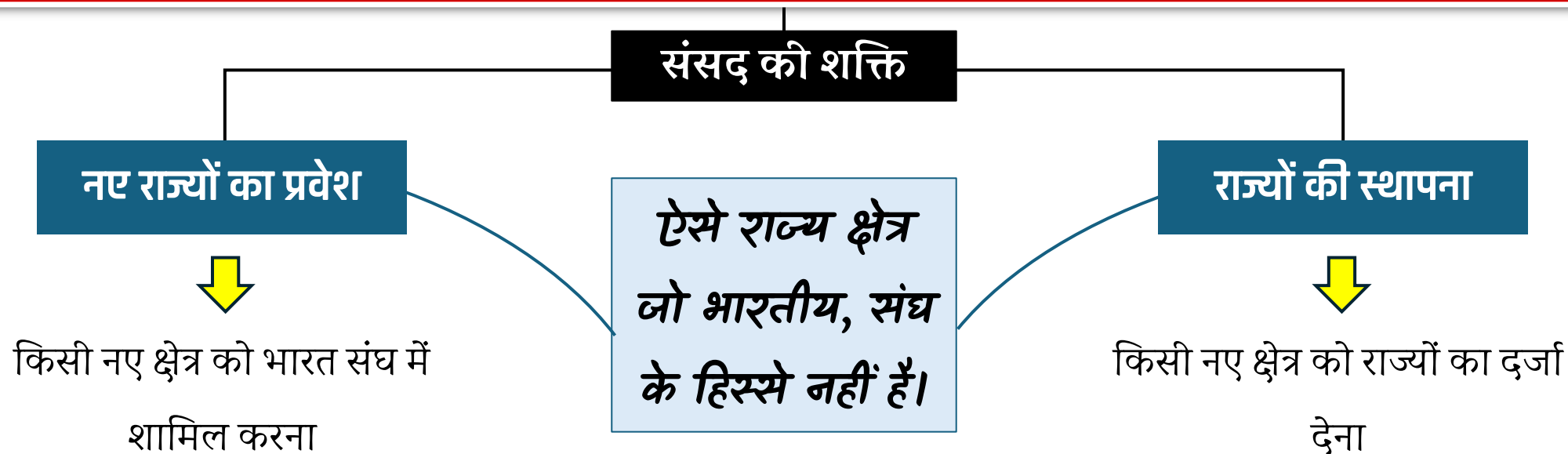
Article 1 : Name and Territory of the Union

- 1) **Formal Names of the Country**
 - Bharat
 - India

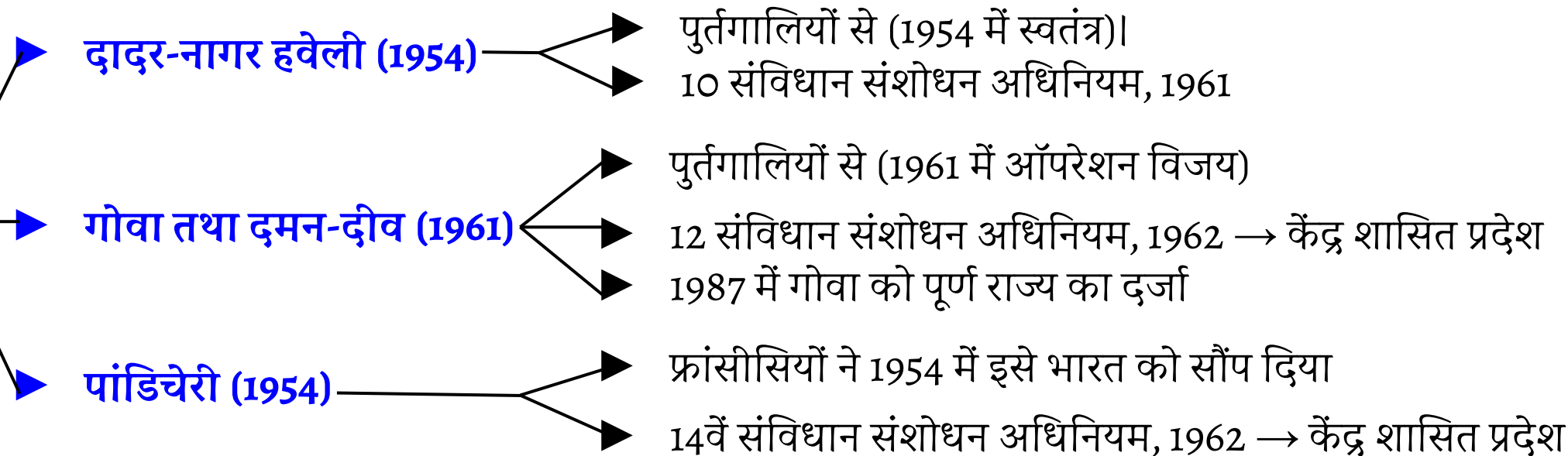
1(1): "India, that is Bharat, shall be a Union of States"
- 2) **States and their Territories**
 - First Schedule
 - Union $\Rightarrow$ States only
 - Territory $\Rightarrow$ States + Union Territories + Acquired territories
- 3) **Union of States**
 - Type of Governance/Polity
 - Influenced by Canada
 - Union of States ✓
 - Federation of States ✗

- *Not the result of an agreement*
 - *States have no right to secede from the Union*
 - *An indestructible Union of destructible States*

अनुच्छेद 2 — नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Admission or Establishment of New States)



भारत अंतरराष्ट्रीय विधि की मान्य रीतियों से नया राज्यक्षेत्र अर्जित कर सकता है — समर्पण, अधिग्रहण / कब्जा, विजय



Article 2 — Admission or Establishment of New States

Powers of Parliament

Admission of New States



Including a new territory in
the Indian Union

Establishment of States



Granting statehood to a new
territory

*Territories that
are not part of
the Indian Union*

India can acquire
new territory
through
recognized
methods of
international law
— Cession,
Occupation/Conq
uest, Victory

➤ **Dadra and Nagar Haveli (1954)**

From the Portuguese (liberated in 1954)
10th Constitutional Amendment Act, 1961

➤ **Goa and Daman & Diu (1961)**

From the Portuguese (Operation Vijay in 1961)
12th Constitutional Amendment Act, 1962 → UT
Goa granted full statehood in 1987

➤ **Puducherry (1954)**

The French handed it over to India in 1954
14th Constitutional Amendment Act, 1962 → Union Territory

SIKKIM

सिक्किम का भारत में विलय : समयरेखा



1



1947 →
चोग्याल राजवंश के
राजा ताशी नामग्याल

2



5 दिसंबर 1950 →
भारत का संरक्षित राज्य
(Protectorate State)

3



1963 →
पालडेन नामग्याल
नए राजा बने।
अमेरिकी महिला होप
कुक से शादी की थी।

4



अप्रैल 1973 →
महल के बाहर हजारों
लोगों ने हिंसक
प्रदर्शन किया

5



1974 →
सिक्किम में पहली बार
चुनाव →
काजी ल्हेंडुप दोरजी

6



35वाँ संशोधन 1974 →
अनुच्छेद 2A →
भारत का
सहयोगी राज्य

7



जनमत संग्रह
(Referendum) →
14 अप्रैल 1975

8



36वाँ संशोधन 1975 →
अनुच्छेद 2A की समाप्ति →
सिक्किम को भारत का
22वाँ पूर्ण राज्य

9



भारत के राष्ट्रपति
फखरुद्दीन अली अहमद ने
इस ऐतिहासिक संशोधन पर
दस्तखत किए

10



16 मई 1975 →
सिक्किम का भारत में
आधिकारिक विलय

Sikkim's Merger with India: Timeline

SIKKIM

1



1947 →
Tashi Namgyal,
the Chogyal ruler
of Sikkim

2



5 December 1950 →
Protectorate State
of India

3



1963 →
Palden Namgyal
became the new king.
He was married to
the American woman
Hope Cooke.

4



April 1973 →
Thousands of people
staged violent protests
outside the palace.

5



1974 →
First election
in Sikkim →
Kazi Lhendup Dorji

6



35th Amendment, 1974 →
Article 2A →
Sikkim became an
Associate State of India

7



Referendum →
14 April 1975

8



36th Amendment, 1975 →
Article 2A ended →
Sikkim became the
22nd full state of India

9



President of India
Fakhruddin Ali Ahmed
signed this historic
amendment.

10



16 May 1975 →
Official merger of
Sikkim with India

अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States)

साधारण बहुमत द्वारा पारित → 368 का प्रयोग नहीं

संसद की शक्ति

लागू - जो क्षेत्र भारत का हिस्सा है

1) संसद विधि द्वारा

- नए राज्यों का निर्माण
- राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि
- राज्यों के क्षेत्र में कमी
- राज्य की सीमाओं में परिवर्तन
- राज्य के नाम में परिवर्तन

2) राज्यों के पुनर्गठन हेतु ⇒ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है

- यदि विधेयक किसी राज्य को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य विधानमंडल को उसकी राय जानने हेतु, एक निर्धारित अवधि के भीतर, भेजेंगे।
 - ✓ पाँचवा संविधान संशोधन 1955
- राष्ट्रपति/संसद राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य नहीं है।
 - ✓ राज्य विधानमंडल राय न भी दे, तो भी निर्धारित अवधि के बाद संसद आगे बढ़ सकती है।
- UTs के मामले में विधानमंडल को भेजना आवश्यक नहीं है।

Article 3 : Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States

Passed by a simple majority → Article 368 not applicable

Powers of Parliament

Applicable - to territories that are already a part of India

1) By Parliamentary Law

- Formation of new states
- Increase in the area of states
- Decrease in the area of states
- Alteration of boundaries of states
- Change in the name of a state

2) For reorganization of states ⇒ Prior recommendation of the President is necessary

- If a Bill affects any State, the President shall refer it to the concerned State Legislature for its opinion within a specified period.

✓ Fifth Amendment 1955

- The President/Parliament is **not bound** by the opinion of the State Legislature.
- ✓ Even if the State Legislature does not give its opinion, Parliament can proceed after the specified period.
- In the case of UTs, referral to the Legislature is not necessary.

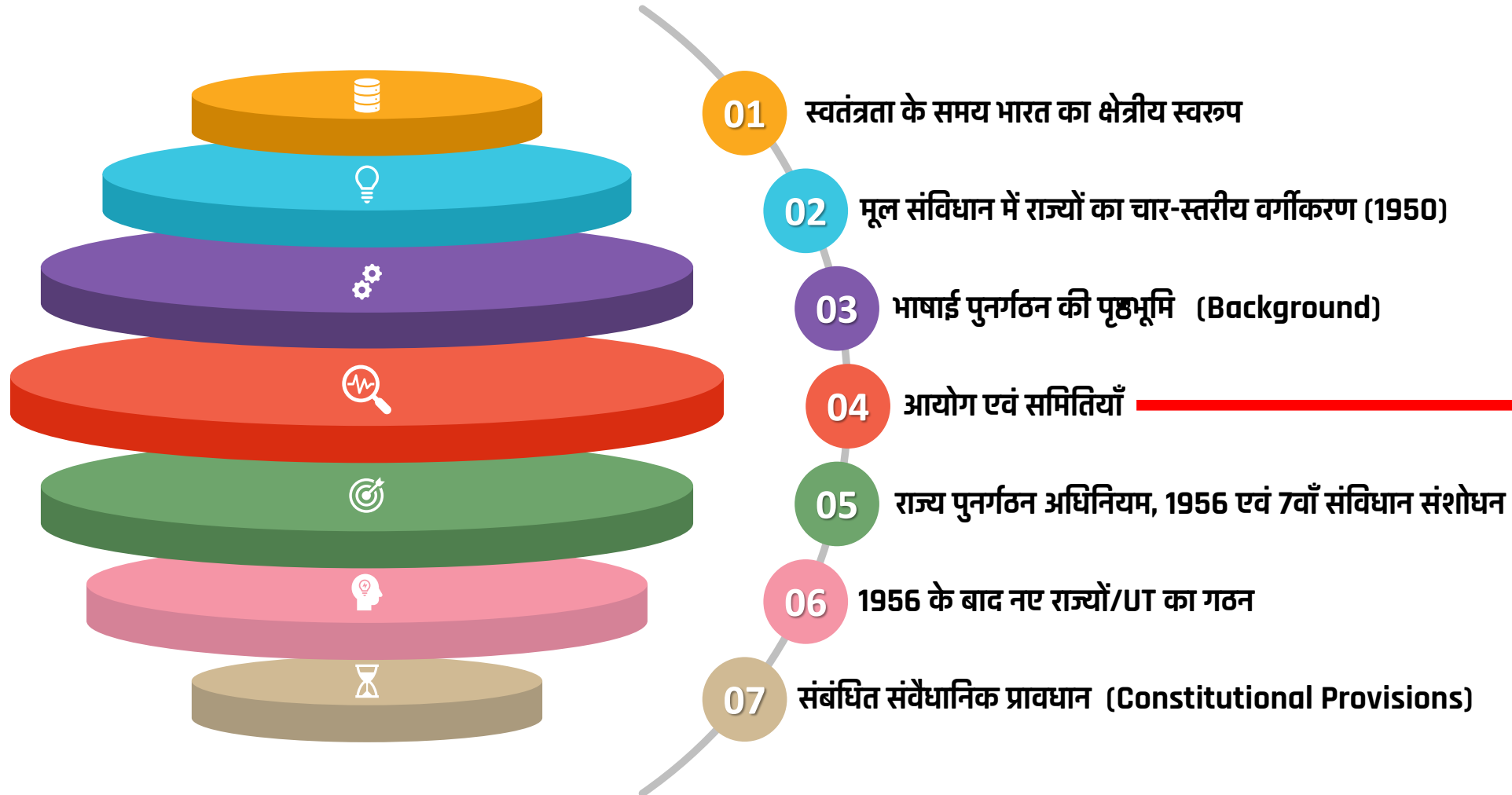
अनुच्छेद 4 : पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।

- 1) **अनुच्छेद 4:** नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2) और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3) के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाएगा।
 - ✓ यह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर होगा।
 - ✓ यह साधारण बहुमत से होता है।
- 2) **क्या भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकता है?**
 - बेरुबारी संघ मामला (1960) → संसद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को नहीं सौंप सकती।
 - इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा।
 - उदाहरण के लिए: 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

Article 4 : Laws made under Articles 2 and 3 for the purpose of providing for the amendment of the First Schedule and the Fourth Schedule and for supplemental, incidental and consequential matters.

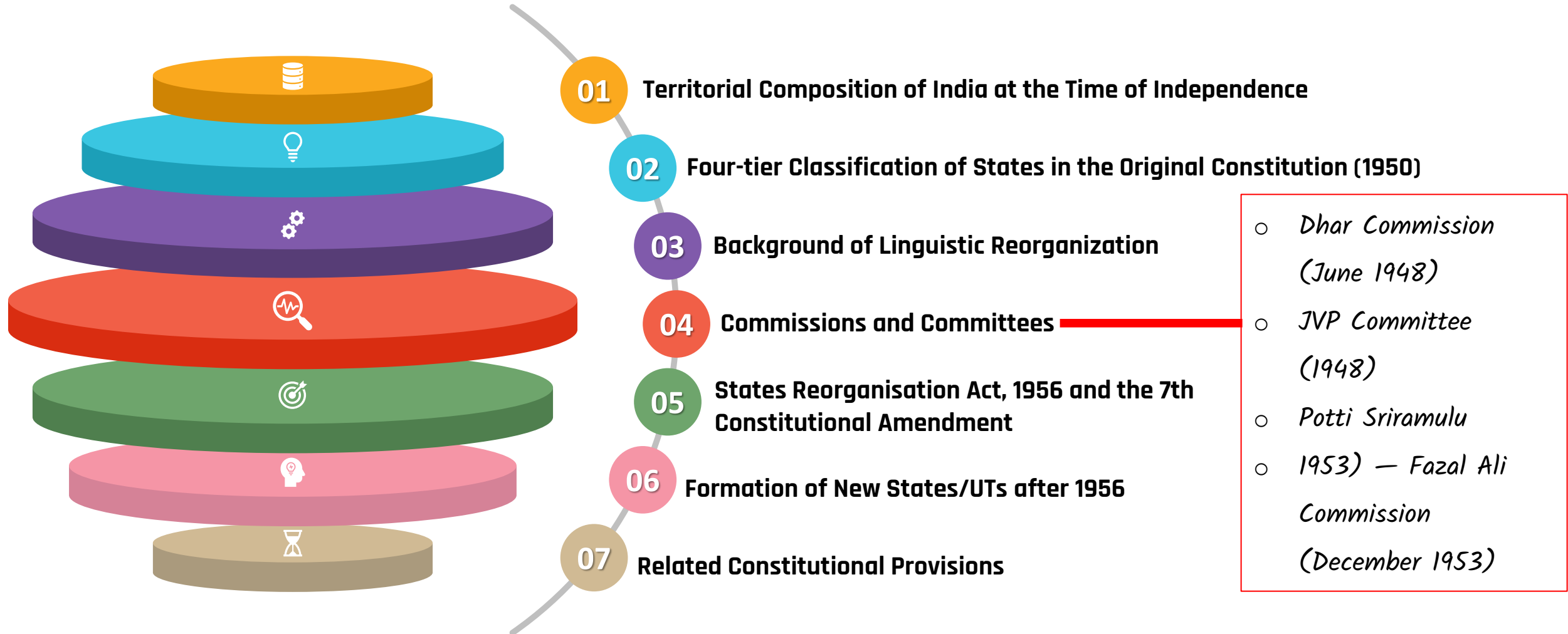
- 1) **Article 4** : Any law enacted by Parliament regarding the admission or establishment of new states (Article 2), or the formation of new states and alteration of areas, boundaries, or names of existing states (Article 3), **will not be** considered a 'constitutional amendment' **under Article 368..**
 - ✓ It is passed by a simple majority
- 2) **Can India cede its territory to another country?**
 - Berubari Union Case (1960) : Parliament cannot cede Indian territory to a foreign country by simple majority under Art 3.
 - A constitutional amendment under Article 368 is mandatory for this.
 - Example : 100th Constitutional Amendment Act, by which territories were exchanged between India and Bangladesh.

3) राज्यों का पुनर्गठन (Reorganization of States)



- धर आयोग (जून 1948)
- JVP समिति (1948)
- पोद्दी श्रीरामुलु
- फजल अली आयोग (दिसंबर 1953)

3) Reorganization of States



3.4) आयोग एवं समितियाँ (Commissions & Committees)

1) धर आयोग (Dhar Commission) : जून 1948

- अध्यक्ष → जस्टिस एस.के. धर
- इसे प्रथम भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं।
- रिपोर्ट (दिसम्बर 1948) : पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा व भौगोलिक समीपता के आधार पर हो।
- परिणाम : भाषाई समूहों में व्यापक असंतोष।

2) JVP समिति (JVP Committee) : 1948-49

- धर आयोग के असंतोष पर विचार हेतु कांग्रेस ने दिसम्बर 1948 में गठित की; रिपोर्ट अप्रैल 1949
- निष्कर्ष : समिति ने भी भाषा को आधार अस्वीकार किया — राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा व आर्थिक हितों को प्राथमिकता; परन्तु प्रबल जनदबाव पर पुनर्विचार का संकेत।

J V P	सदस्य
J	जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru)
V	वल्लभभाई पटेल (Vallabhbhai Patel)
P	पट्टाभि सीतारमैया (Pattabhi Sitaramayya)

3.4) Commissions & Committees

1) Dhar Commission : june 1948

- The Dhar Commission was chaired by Justice S.K. Dhar.
- It is also known as the First Linguistic Provinces Commission.
- The report (December 1948) recommended that reorganisation should be based not on language, but on administrative convenience and geographical contiguity.
- This resulted in widespread dissatisfaction among linguistic groups.

2) JVP Committee : 1948–49

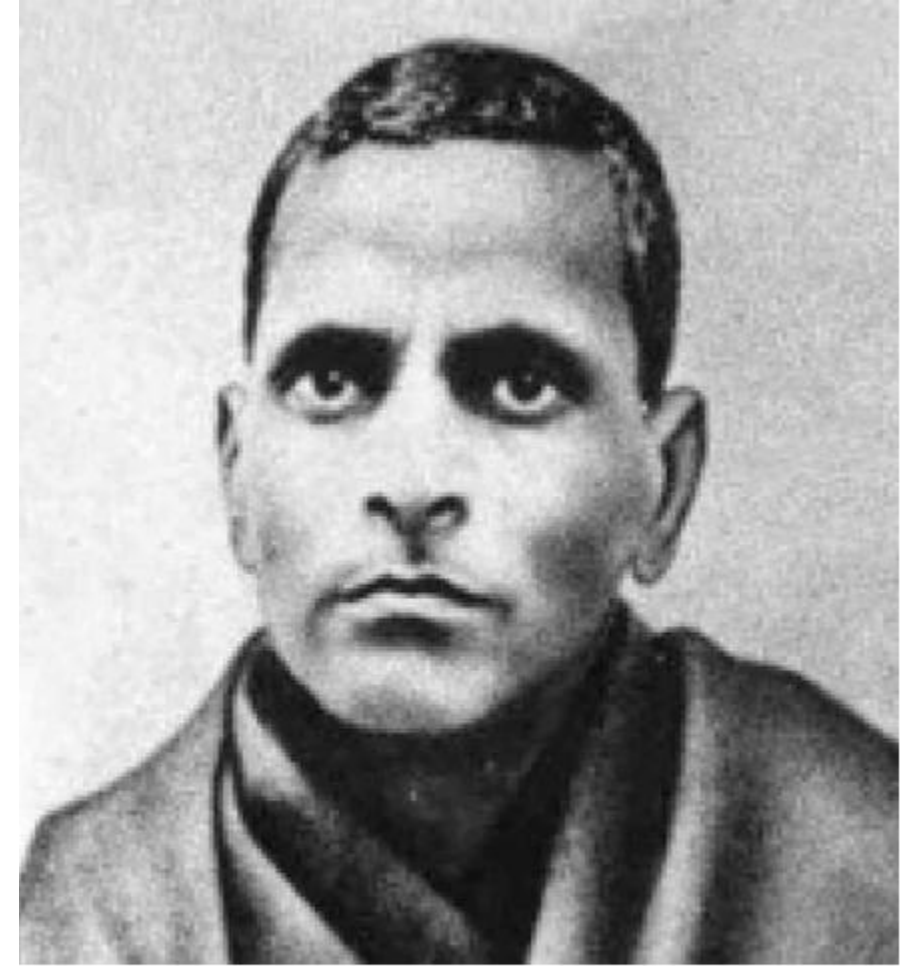
- In view of the dissatisfaction over the Dhar Commission, Congress constituted the JVP Committee in December 1948; its report was submitted in April 1949.
- The committee also rejected language as the basis and gave priority to national unity, security and economic interests; however, it hinted at reconsideration under strong public pressure.

J V P	Member
J	Jawaharlal Nehru
V	Vallabhbhai Patel
P	Pattabhi Sitaramayya

3) पोद्दी श्रीरामुलु एवं आन्ध्र आंदोलन - पहला भाषाई राज्य

- माँग : तेलुगुभाषी लोगों हेतु मद्रास से पृथक् आन्ध्र राज्य।
- आमरण अनशन :
 - ✓ 19 अक्टूबर 1952 → 15 दिसम्बर 1952 (निधन : लगभग 58 दिन)
 - ✓ उपाधि — 'अमरजीवी'।
- जन-आक्रोश पर नेहरू ने 19 दिसम्बर 1952 को पृथक् आन्ध्र राज्य की घोषणा की।
- आन्ध्र राज्य का गठन : 1 अक्टूबर 1953 — मद्रास के तेलुगुभाषी (उत्तरी) जिलों से; राजधानी कर्नूल। यह भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य।

- 1953 का आन्ध्र राज्य और 1956 का आन्ध्र प्रदेश अलग हैं।
- 1 नवम्बर 1956 को आन्ध्र राज्य + हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बना (राजधानी हैदराबाद)।



Amarajeevi Potti Sreeramulu!
Father of Andhra (divided from
Madras presidency)

3) Potti Sriramulu & Andhra Movement — First Linguistic State

- The demand was raised for a separate Andhra state for Telugu-speaking people, carved out of Madras.
- **Potti Sriramulu began his fast unto death on 19 October 1952 and passed away approximately 58 days later on 15 December 1952.**
 - ✓ He was conferred the title 'Amarajivi' (Immortal Soul).'
- In response to public outrage, Nehru announced a separate Andhra state on 19 December 1952
- Andhra State was formed on 1 October 1953 from the Telugu-speaking (northern) districts of Madras; its capital was Kurnool. It was India's first state formed on a linguistic basis.



**Amarajeevi Potti Sreeramulu!
Father of Andhra (divided from
Madras presidency)**

- The Andhra State of 1953 and Andhra Pradesh of 1956 are distinct entities.
- On 1 November 1956, Andhra State was merged with the Telangana region of Hyderabad to form Andhra Pradesh; Hyderabad became the capital.

4) फजल अली आयोग - राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953

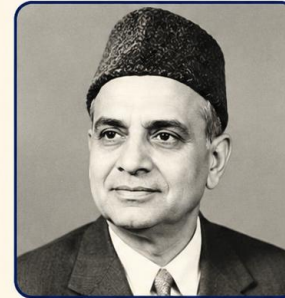
- 29 दिसम्बर 1953 (पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद)
- **सदस्य (3) :**
 - ✓ फजल अली (अध्यक्ष)
 - ✓ के.एम. पणिकर
 - ✓ हृदयनाथ कुंजरू
- **रिपोर्ट :** 30 सितम्बर 1955।
- आयोग ने चार-स्तरीय वर्गीकरण समाप्त करने की सिफारिश की।
- **सिफारिश :** 16 राज्य + 3 UT
 - ✓ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 → 1 नवम्बर 1956
 - ✓ 7वाँ संविधान संशोधन
 - ✓ कार्यान्वयन में अंततः → 14 राज्य + 6 UT

फजल अली आयोग - राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC), 1953

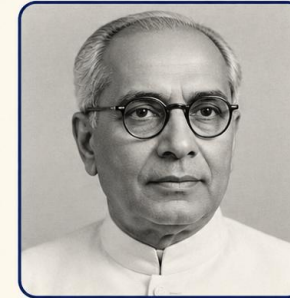


दिसम्बर 1953 (पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद)

सदस्य (3) :



फजल अली
(अध्यक्ष)



के.एम. पणिकर



हृदयनाथ कुंजरू



रिपोर्ट : 30 सितम्बर 1955।

#	कारक
1	देश की एकता एवं अखंडता
2	भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता
3	वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
4	जन-कल्याणकारी योजनाएँ

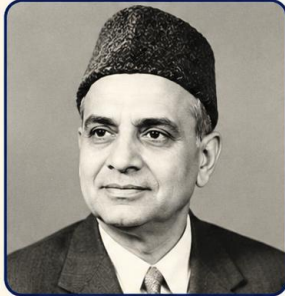
4) **Fazal Ali Commission — States Reorganisation Commission, 1953**

- The Fazal Ali Commission was constituted on 29 December 1953, after the death of Potti Sriramulu
- **members (3) :**
 - ✓ Fazal Ali (Chairman), K.M. Panikkar, and Hriday Nath Kunzru.
- The Commission submitted its report on 30 September 1955.
- The Commission recommended abolition of the four-tier classification of states.
- The Commission recommended 16 States and 3 Union Territories.
 - ✓ The 7th Constitutional Amendment was enacted under the States Reorganisation Act, 1956.
 - ✓ The Act came into effect on 1 November 1956.
 - ✓ As a result of its implementation, 14 States and 6 Union Territories ultimately came into existence.

फजल अली आयोग - राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC), 1953

**दिसम्बर 1953** (पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद)

सदस्य (3) :



फजल अली
(अध्यक्ष)



के.एम. पणिकर



हृदयनाथ कुंजुरु

**रिपोर्ट : 30 सितम्बर 1955।**

#	Factors
1	Unity and Integrity of the Nation
2	Linguistic and Cultural Uniformity
3	Financial, Economic and Administrative System
4	Public Welfare Schemes

3.5) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 एवं 7वाँ संविधान संशोधन

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956

पुराना वर्गीकरण समाप्त	राज्यों का 'भाग क, ख, ग, घ' (Part A, B, C, D) वर्गीकरण पूरी तरह समाप्त कर दिया गया।
नई संरचना	देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में पुनर्गठित किया गया।
प्रमुख विलय	मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर एक नया राज्य मध्य प्रदेश बनाया गया।
अन्य विलय	अजमेर को राजस्थान में, सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे में, तथा कुर्ग को मैसूर में मिलाया गया।
नया राज्य	हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया।

7वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1956

अनुच्छेद 1 व अनुसूची 1	राज्यों का नया वर्गीकरण (राज्य और केंद्र शासित प्रदेश)।
भाग 7 निरस्त	संविधान का भाग 7, जो 'भाग ख' राज्यों से संबंधित था,
राज्यपाल (153)	अब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
उच्च न्यायालय (231)	संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक 'साझा उच्च न्यायालय' स्थापित करने का अधिकार मिला।
UTs का प्रशासन	केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया।
भाषाई अल्पसंख्यक	अनुच्छेद 350A (मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा) और 350B (विशेष अधिकारी की नियुक्ति) जोड़े गए।

1.	आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953
2.	गुजरात	1 मई, 1960
3.	नगालैंड	1 दिसंबर, 1963
4.	हरियाणा	1 नवंबर, 1966
5.	हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971
6.	मेघालय	21 जनवरी, 1972
7.	मणिपुर	21 जनवरी, 1972
8.	त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972
9.	सिक्किम	16 मई, 1975
10.	मिजोरम	20 फरवरी, 1987
11.	अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
12.	गोवा	30 मई, 1987
13.	छत्तीसगढ़	1 नवंबर, 2000
14.	उत्तराखंड	9 नवंबर, 2000
15.	झारखंड	15 नवंबर, 2000
16.	तेलंगाना	2 जून, 2014

1.	Andhra Pradesh	1 October, 1953
2.	Gujarat	1 May, 1960
3.	Nagaland	1 December, 1963
4.	Haryana	1 November, 1966
5.	Himachal Pradesh	25 January, 1971
6.	Meghalaya	21 January, 1972
7.	Manipur	21 January, 1972
8.	Tripura	21 January, 1972
9.	Sikkim	16 May, 1975
10.	Mizoram	20 February, 1987
11.	Arunachal Pradesh	20 February, 1987
12.	Goa	30 May, 1987
13.	Chhattisgarh	1 November, 2000
14.	Uttarakhand	9 November, 2000
15.	Jharkhand	15 November, 2000
16.	Telangana	2 June, 2014



भारत में राज्यों के लिए किए गए विशेष उपबंध (अनुच्छेद 371 से 371J तक)



याद करने की ट्रिक

**“महा-गुजरात में नागा, असम-मणि;
आंध्र दो बार, फिर
सिक्किम-मिजो-अरुण-गोवा-कर्नाटक”**

क्रम याद रखें



A से J Super Trick

A = A Nagaland
B = B Assam
C = C Manipur
D-E = Andhra/Telangana → Andhra
F = Sikkim
G = Mizoram
H = Arunachal
I = Goa
J = Karnataka

महत्वपूर्ण Pair

371A — Nagaland
Naga customs +
Land & Resources

371G — Mizoram
Mizo customs +
Land

A और G को Pair में याद करें

ध्यान रखें

Article 370 =
जम्मू-कश्मीर

Article 371–371J =
अन्य राज्यों के लिए
विशेष उपबंध

370 को 371-series की
राज्य-सूची में mix न करें।

अनुच्छेद	राज्य	मुख्य विशेष प्रावधान
371	महाराष्ट्र + गुजरात	- कुछ क्षेत्रों के लिए अलग Development Boards का प्रावधान - विकास निधि तथा तकनीकी शिक्षा/रोजगार में संतुलित अवसर
371A	नागालैंड	- नागाओं की धार्मिक-सामाजिक प्रथाएँ, customary law, customary justice तथा - भूमि एवं उसके संसाधनों पर विशेष संरक्षण
371B	असम	विधानसभा में Tribal Areas Committee के गठन का प्रावधान
371C	मणिपुर	- Hill Areas Committee का प्रावधान तथा - राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी
371D	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकारी रोजगार एवं शिक्षा में समान अवसर/सुविधाएँ
371E	आंध्र प्रदेश	संसद द्वारा Central University स्थापित करने का प्रावधान
371F	सिक्किम	सिक्किम के भारत में विलय से जुड़े विशेष प्रावधान; विभिन्न वर्गों के हितों की सुरक्षा
371G	मिजोरम	- मिजो धार्मिक-सामाजिक प्रथाएँ, customary law, customary justice तथा - भूमि के स्वामित्व/हस्तांतरण पर विशेष संरक्षण
371H	अरुणाचल प्रदेश	- Law & Order के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी - विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य
371I	गोवा	विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य
371J	कर्नाटक	- विशेष क्षेत्र के लिए Development Board - विकास निधि तथा शिक्षा एवं सरकारी रोजगार में विशेष अवसर/आरक्षण का प्रावधान

★ One-Line Revision : 371 MH-GJ | A Naga | B Assam | C Manipur | D AP-Telangana | E AP | F Sikkim | G Mizoram | H Arunachal | I Goa | J Karnataka



SPECIAL PROVISIONS FOR STATES IN INDIA (ARTICLES 371 TO 371J)



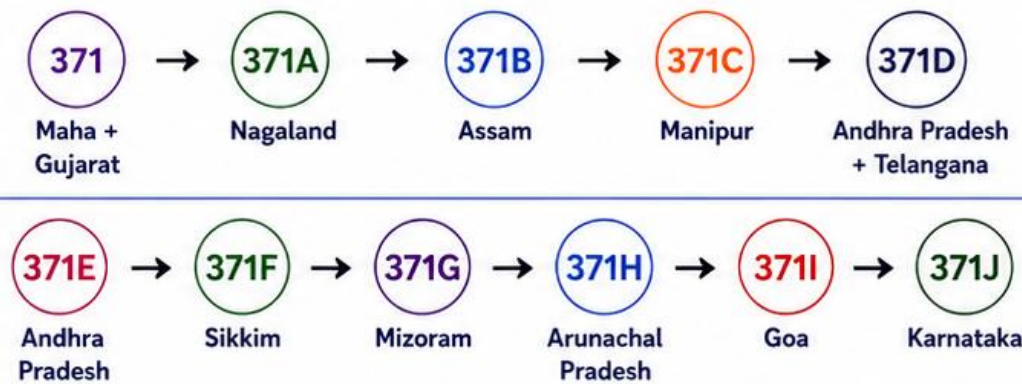
सत्यमेव जयते

ARTICLE	STATE(S)	KEY SPECIAL PROVISION
371	Maharashtra & Gujarat	- Provision for separate Development Boards for certain areas. - Equitable distribution of funds for development and balanced opportunities in education & employment.
371A	Nagaland	- Protection of Naga religious & social practices, customary law, customary justice. - Protection of land & its resources.
371B	Assam	Provision for the creation of a Tribal Areas Committee in the Legislative Assembly.
371C	Manipur	- Provision for Hill Areas Committee. - Special responsibility of the Governor.
371D	Andhra Pradesh & Telangana	Equitable opportunities & facilities in matters of public employment and education for people of different areas.
371E	Andhra Pradesh	Provision for establishment of a Central University by Parliament.
371F	Sikkim	Special provisions relating to the merger of Sikkim with India and protection of interests of different sections of people.
371G	Mizoram	- Protection of Mizo religious & social practices, customary law, customary justice. - Protection regarding ownership & transfer of land.
371H	Arunachal Pradesh	- Special responsibility of the Governor in respect of law & order. - Legislative Assembly to have not less than 30 members.
371I	Goa	Legislative Assembly to have not less than 30 members.
371J	Karnataka	- Provision for Development Board for a special region. - Equitable opportunities in education and reservation in matters of public employment.

EASY MEMORY TRICK

“Maha-Gujarat has Naga, Assam-Mani;
Andhra twice, then Sikkim-Mizo-Arun-Goa-Karnataka.”

REMEMBER IN SEQUENCE



A to J SUPER TRICK

A = A Nagaland
B = B Assam
C = C Manipur
D-E = Andhra/Telangana → Andhra
F = Sikkim
G = Mizoram
H = Arunachal
I = Goa
J = Karnataka



IMPORTANT PAIR

371A — Nagaland
Naga customs +
Land & Resources

↔

371G — Mizoram
Mizo customs +
Land

Remember A and G as a Pair!

IMPORTANT NOTE



Article 370 = Jammu & Kashmir

Articles 371–371J = Special provisions for other states.

Do not mix Article 370 with 371-series.

★ ONE-LINE REVISION :

371 MH-GJ | A Naga | B Assam | C Manipur | D AP-Telangana | E AP | F Sikkim | G Mizoram | H Arunachal | I Goa | J Karnataka